एक और तो आप पाते हैं कि नीति परिवर्तन अत्यन्त जोखिम भरे हैं। हम देखते हैं कि नीति परिवर्तन वित्तीय निगमों को अधिकाधिक ऋण लेने की अनुमति देने हेतु किए जाते हैं और उसी के साथ-साथ हम इस शर्त-विशेष में छूट दे रहे हैं कि वित्तीय निगमों द्वारा जारी किए गए ऋण-पत्रों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिभूति करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था के वित्तीय पक्ष के लिए अच्छा नहीं होगा और इसलिए सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

इस चेतावनी के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

5.13 म० प०

प्रधान मंत्री की हाल की विदेश यात्रा के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभा के गत सत्र के बाद अपनी विदेश यात्राओं के बारे एक वक्तव्य देने और माननीय सदस्यों को, जिन देशों की मैंने यात्रा की, उनके नेताओं से हुई अपनी बातचीत का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं।

मैंने 21 से 26 मई तक सोवियत संघ की राजकीय यात्रा की और वहां से एक दिन के लिए 2 जून को बंगलादेश चला गया। 5 जून से 18 जून तक मैंने मिस्र, फ्रांस, अल्जीरिया, संयुक्त राज्य अमरीका और स्विटजरलैंड में जेनेवा का दौरा किया।

जैसा कि सभा को मालूम है कि सोवियत संघ के साथ हमारे सम्बन्ध सदैव से ही बहुत अच्छे रहे हैं और मेरी यात्रा से उस देश के साथ हमारी मैत्री और पारस्परिक सहयोग की भावना और मजबूत हुई है।

सोवियत संघ में, मेरा विशेष रूप से गर्मजोशी के साथ सत्कार किया गया और मेरी सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के महासचिव श्री मिखाइल गर्बाचेव के साथ अनेक बैठकें ई जिसमें उन्होंने इस बात को दोहराया कि सोवियत संघ भारत के साथ उच्च स्तरीय सम्पर्क को महत्व देता है और भारत के साथ मित्रता का विस्तार करना चाहता है। मैंने भी भारत की जनता और सरकार द्वारा आपसी सम्बन्धों को दिए जाने वाले उच्च महत्व का उल्लेख किया।

हमारी बातचीत बहुत ही सौहार्दपूर्ण और व्यापक रूप से हुई जिसमें द्विपक्षीय सम्बन्धों और महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मामलों को लिया गया था। जहां तक सोवियत संघ और भारत के बीच सम्बन्धों का प्रश्न है, हम विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे वर्तमान सहयोग को बढ़ाने और उसे दीर्घ-कालीन बनाने पर सहमत हुए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर जो चर्चा हुई इसमें विश्व शान्ति और निरस्त्रीकरण, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया, पश्चिम एशिया, ईरान और इराक की घटनाएं शामिल थीं। हमने उनसे उन प्रयासों का उल्लेख किया जो हम अपने पड़ौसी देशों के साथ मित्रता बढ़ाने के लिए कर रहे हैं और गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के चेयरमैन के रूप में जो पहल कर रहे हैं। मैं सोवियत संघ की मन्त्री परिषद के चेयरमैन, श्री निकोलई तिखोनोव, भूतपूर्व विदेश मंत्री

और अब सोवियत संघ के राष्ट्रपति श्री अन्द्रेई ग्रोमिको तथा अन्य नेताओं से मिला।

मेरी यात्रा के अन्त में जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य में हमारी बातचीत के परिणाम को दर्शाया गया है। दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रथम सझौता आर्थिक और तकनीकी सहयोग के बारे में था, जिसके अन्तर्गत सोवियत संघ हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं विशेषकर बिजली, कोयला और पेट्रोलियम क्षेत्र की परियोजनाओं में सहयोग करेगा। लौह और इस्पात तथा मशीन निर्माण क्षेत्रों में भी सोवियत सहयोग का प्रावधान किया गया है। इस समझौते को पूरा करने के लिए सोवियत संघ एक बिलियन रूबल का ऋण देगा।

दूसरे जिस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, वह मुख्यतः हमारे दोनों देशों के बीच सन्, 2000 तक चलने वाले आर्थिक विषयों व्यापार, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के बारे में था।

मेरे कार्यक्रम में बाइलोरशयन गणतन्त्र केमिन्सक और किरघिज गणतन्त्र के फरून्जे का दौरा भी सम्मिलित था। सोवियत मित्रता सोसाइटीज संघ और सोवियत भारत मित्रता सोसाइटी द्वारा मास्को में आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में हमारी भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को मरणोपरान्त लेनिन शक्ति पुरस्कार दिया गया और मास्को में एक चौक का नाम भी उनके नाम पर रखा गया।

मेरे आकलन अनुसार, सोवियत संघ के नेतृत्व द्वारा हमारे विचारों को समझने तथा भारत-सोवियत सदभावना और सहयोग को सौहार्दता के नये स्तर पर पहुंचाने में यह यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण रही है।

2 जून को बंगलादेश की यात्रा पर जाने का मेरा उद्देश्य, वहां तूफान के कारण हुए भारी सर्वनाश पर वहां की सरकार और जनता के प्रति भारत की विनम्र सहानुभूति प्रकट करना था। श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री जयवर्द्धने महोदय भी, जो कि बातचीत के लिए दिल्ली आए हुए थे, मेरे साथ बंगलादेश गये। हमने बंगलादेश गणतन्त्र के राष्ट्रपति लै० जनरल इरशाद से बातचीत की। यह यात्रा दक्षिण एशिया के देशों के बीच पनप रही एकता की भावना की भी अभिव्यक्ति थी।

गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में मिस्र और अल्जरिया हमारे बहुत घनिष्ठ सहयोगी रहे हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी को अप्रैल, 1984 में दोनों देशों की यात्रा पर जाना था, परन्तु नहीं जा सकीं। जब मैंने पदभार संभाला तो उन्होंने नये सिर से निमन्त्रण भेजे।

काहिरा में, राष्ट्रपति हुसनी मुबारक ने बड़ी ही गर्म जोशी और सौहार्दता से मेरा स्वागत किया और दोनों ही अन्तर्राष्ट्रीय तथा पारस्परिक मामलों पर गहराई से वार्तालाप किया। मिस्र ने विशेष रूप से गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की हमारी अध्यक्षता, निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने में हमारी भूमिका तथा ईरान-इराक युद्ध की शीघ्र समाप्ति हेतु किए गए हमारे प्रयासों की सराहना की। एक दूसरे के निकट सहयोग करने और पश्चिम एशिया के प्रश्न पर सम्पर्क बनाए रखने की आवश्यकता पर एक समझौता हुआ। हमने पारस्परिक आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग को अधिकाधिक बढ़ाने की आवश्यकता पर भी समझौता किया। यह निर्णय किया गया कि अक्तूबर, 1985 में, भारत

मिस्र संयुक्त आयोग की सम्भावित प्रथम बैठक में सम्भावनाओं का और अधिक ठोस रूप से पता लगाया जाय। मैंने मिस्र के प्रधान मंत्री श्री कमाल हसन अली महोदय से भी बातचीत की।

अल्जीरिया में, मैंने राष्ट्रपति श्री चान्दली बेन्डजेडीड महोदय से पारस्परिक और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर विस्तार से बातचीत की। बातचीत बड़ी मैत्रीपूर्ण और उन्मुक्त वातावरण में हुई। आपसी हित के अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर विचारों में समानता थी और हम विशेषकर गुट-निरपेक्ष मामलों पर निकट सम्पर्क बनाए रखने पर सहमत हुए। यह समझौता भी हुआ कि दोनों देशों के विदेश कार्यालयों के मध्य प्रतिवर्ष वैकल्पिक रूप से अल्जीयर्स और नई दिल्ली में विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक ऐसी संस्था बनायी जाए जो यह कार्य करे। मैंने वहां के प्रधान मंत्री श्री अब्देलहमीद ब्राहीमी से भी बातचीत की।

दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए हमने अल्जीरिया से पांच लाख टन कच्चे तेल खरीदना स्वीकार किया। अल्जीरिया भारत को व्यापारिक ठेकों और परियोजनाओं के मामले में उच्च प्राथमिकता देने को तैयार है।

पश्चिमी सहारा के प्रश्न पर हमने पोलिसारियो के प्रति अपनी सहानुभूति और समर्थन को दोहराया।

मुझसे एस० ए० डी० आर० के प्रधान मंत्री और पोलिसारियो की कार्यकारणी के सदस्य श्री महफूद अली बेलबा मिले। उन्हें यह बताया गया कि नवम्बर, 1984 में 20 वें ओ० ए० यू० शिखर सम्मेलन में एस० ए० डी० आर० के भाग लेने के बाद से, हमारे सम्बन्धों का दर्जा बढ़ा है पर सक्रिय रूप से विचार किया जाता रहा है।

फ्रांस की मेरी यात्रा, जनवरी, 1980 में राष्ट्रपति गिस्कार्ड डी इस्टेंग की भारत यात्रा, नवम्बर, 1981 में स्व० प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की फ्रांस यात्रा, नवम्बर, 1982 में राष्ट्रपति मित्तरां की भारत यात्रा तथा सितम्बर, 1983 में श्रीमती इंदिरा गांधी का पेरिस में यात्रा-मध्य में रुकने से लेकर उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान की एक अगली कड़ी है। मेरी यात्रा बहुत उपयोगी सिद्ध हुई और अधिक गतिशील पारिस्परिक सम्बन्धों की नींव और मजबूत हुई।

राष्ट्रपति मितरां और मैंने विश्व स्थिति और अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा देने तथा विकसित एवं विकासशील देशों के बीच और अधिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए महती आवश्यकता का जायजा लिया। मैंने वहां के प्रधान मंत्री श्री लौरेन्ट फेबियस से भी विस्तृत बातचीत की।

अपनी बैठकों में, मैंने अपने पारस्परिक सम्बन्धों के राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं को सन्तुलित ढंग से विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। फ्रांसीसियों ने हमारी विचारधारा के प्रति उल्लेखनीय स्वागत भाव प्रदर्शित किया गया।

यात्रा के दौरान, फ्रांस से हमारे दो समझौते हुए हैं; जिनमें एक है भारत में उच्च स्तरीय अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारत-फ्रांस केन्द्र स्थापित करना और दूसरे समझौते में शहरी मलबे को ऊर्जा में बदलने और गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने में फ्रांसीसी सहयोग का प्रस्ताव। अनेक क्षेत्रों में, सर्वांगीण भारत-फ्रांस आर्थिक सहयोग के उल्लेखनीय रूप से आगे बढ़ने की आशा है।

मैंने 7 जून को भारत महोत्सव का उद्घाटन किया और जैसा कि सदस्यगण जानते हैं यह महोत्सव सन 1986 के मध्य तक चलेगा और यह फ्रांसीसी जनता पर पहले ही उल्लेखनीय प्रभाव डाल चुका है।

पेरिस में, मैंने 'यूनेस्को' की सम्बोधित किया और वह संस्था जो कार्य कर रही है, उसके प्रति अपना समर्थन दोहराया।

11 से 15 जून तक अमरीका की मेरी यात्रा सर्वाधिक उपयोगी रही।

मुझे महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मामलों तथा परमाणु आयुध तैयार करने की पाकिस्तानी योजनाओं और कुछ आतंकवादी तत्वों के क्रियाकलापों के समाचारों जैसे भारत के लिए तुरन्त चिन्ताजनक मामलों पर भी राष्ट्रपति रीगन से विचारों के आदान-प्रदान का अवसर मिला। बातचीत गर्मजोशी और खुले दिमाग से हुई।

मैंने भारत के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की आतंकवादी हिंसा का मुकाबला करने में राष्ट्रपति द्वारा निकट सहयोग की इच्छा का स्वागत किया

मैंने पाया कि राष्ट्रपति और उनके सलाहकारों में, हम जो कुछ भारत में करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके प्रति बहुत ही भारी रुचि और सदभावना है। कई क्षेत्रों में नीति और दृष्टिकोण विषयक मतभेद होने पर भी मैंने यह अनुभव किया कि हम विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। हम इन उच्च स्तरीय सम्बन्धों को महत्व देते हैं और वार्तालाप को जारी रखना चाहेंगे। मेरा विश्वास है कि अपनी सदभावना और सहयोग को विस्तार देने हेतु इन नीवों पर निर्माण का अच्छा अवसर है।

माननीय सदस्यों ने मेरी अमरीका यात्रा के बाद जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य की विषय-वस्तु को देखा होगा, जिसमें आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग के कुछ क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। हमने तीन वर्षों के लिए और आगे वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय करने, टीका कार्यक्रम आरम्भ करने, दीर्घकालीन अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम तथा वाणिज्यिक प्रौद्योगिकी की प्रगति हेतु कार्यक्रम जैसे सहयोग के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को चुना है।

मुझे कांग्रेस की संयुक्त बैठक को सम्बोधित करने का निमन्त्रण देकर भारत को सम्मानित किया गया। मेरी प्रशासन के अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों के साथ-साथ विख्यात वैज्ञानिकों, प्रेस के नेताओं तथा अमरीका वाणिज्य चैम्बरों से भी बातचीत हुई।

वाशिंगटन और हौस्टन दोनों नगरों में भारतीय समुदाय के साथ समारोह आयोजित किये गये। उप-राष्ट्रपति बुश ने हौस्टन तक मेरे साथ जाने की कृपा की, जहां पर मैंने 'नासा' का संक्षिप्त दौरा किया। मेरे कार्यक्रम की मुख्य घटना थी भारत महोत्सव का औपचारिक उद्घाटन जिसे श्रीमती इंदिरा गांधी की स्मृति को समर्पित किया गया था। राष्ट्रपति रीगन ने इसका इन शब्दों में उल्लेख किया था "एक अभूतपूर्व राष्ट्रव्यापी उत्सव।"

माननीय सदस्यों ने राष्ट्रपति रीगन की हाल ही में हुई शल्य-चिकित्सा के बारे में पढ़ा होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरा सदन राष्ट्रपति रीगन, श्रीमती रीगन और अमरीका की जनता को, राष्ट्रपति महोदय के पूर्ण और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए हमारी शुभ कामनाओं को प्रेषित करने में मेरे साथ है।

अमरीका से वापस आते समय मैं एक दिन जेनेवा में रुका जहां मुझे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को संबोधित करने का अवसर मिला। अपने भाषण में मैंने संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए भारत की वचनबद्धता को दोहराया तथा संपूर्ण संसार में असंगठित श्रमिकों की सेवा में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा महान कार्य करने का अनुरोध किया।

5.25 म० प०

राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक

—जारी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम चर्चा जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में जो स्टेट फाइनेंशियल कारपोरेशन अमेंडमेंट बिल प्रस्तुत किया गया है, इसमें कई नई धाराएं जोड़ी जा रही हैं। आप अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि यह कानून जिस मकसद से बनाया गया था, वह मकसद यह था कि देश में अलग-अलग स्टेट्स के अन्दर इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा इमदाद दी जा सके और देश को खुशहाल बनाने में ज्यादा सहयोग दिया जाए। शुरू में इसके लिए जिस प्रकार की व्यवस्था हुई है, उससे इंडस्ट्रियल डवेलपमेंट काफी हद तक आगे बढ़ा है, मगर इसके बावजूद भी हमें डवेलपमेंट के संबंध में और भी काम करना है। इसके लिए आज जो फाइनेंशियल इंस्टीचूशन्स की हालत है, वह उसके लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए इसके अधिकार क्षेत्र, पैसा, पावर और दूसरी सब चीजों को बढ़ाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए ये जो अमेंडमेंट्स आए हैं, वे निश्चित तरीके से इंडस्ट्रीज के डवेलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। इस प्रकार की व्यवस्था से स्माल स्केल सैक्टर और मीडियम सैक्टर में आगे बढ़ने का बहुत बड़ा अवसर मिलेगा।

5.27 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इन अमेंडमेंट्स के जरिए जिस प्रकार की एक्टिविटीज को बढ़ाने की बात कही गई है, उसमें "इंडस्ट्रियल-कंसर्न" की डैफिनिशन दी गई है :—

[अनुवाद]

"सब प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों की वित्तीय सहायता करना अथवा नौवहन के लिए वित्त की व्यवस्था अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं करेंगी।"